



बांग्लादेश, एक मुक्ति आन्दोलन: भारतीय परिप्रेक्ष्य में

➤ अशोक कुमार¹

सारांश

पाकिस्तान के 1970 के आम चुनाव में आवामी लीग पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी को सत्ता का हस्तान्तरण नहीं हुआ जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब-उर-रहमान के नेतृत्व में एक असहयोग आंदोलन शुरू हो गया जिससे एक गोरिल्ला फोर्स मुक्ति वाहिनी का जन्म हुआ। पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया जिससे लोग अपनी जान बचाने के लिए करोड़ों की संख्या में भारत आ गये। भारत ने इन्हें मानवीय आधार पर शरण दी। 03 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया जिसके जवाब में भारत ने मुक्त वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर जवाबी हमला कर दिया। 1971 का भारत-पाक युद्ध 13 दिनों तक चला। 16 दिसम्बर 1971 को ढाका में जनरल नियाजी ने 93000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार दक्षिण एशिया में बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र और सम्प्रभु राष्ट्र का जन्म हुआ।

मुख्य शब्द- गृहयुद्ध, गोरिल्ला युद्ध, राजकीय भाषा, राजदूत, मेजर जनरल

1. प्रस्तावना

बांग्लादेश एक नदी प्रधान देश है। यहाँ लगभग 700 नदियाँ बहती हैं। बांग्लादेश गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा सुन्दर वन डेल्टा पर स्थित है। इसका विस्तार लगभग 20°35'-26°75' उत्तरी अक्षांश और 88°03'-92°75' पूर्वी देशान्तर तक है। यह विश्व का सबसे सघन आबादी वाला

देश है यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1250 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,47,570 वर्ग कि.मी. है। इसकी कुल जनसंख्या 17.15 करोड़ है। जिसमें 91.04 करोड़ मुसलमान, 7.95 करोड़ हिन्दू, 0.61 करोड़ बौद्ध और 0.30 करोड़ ईसाई धर्मों के लोग रहते हैं।

¹ एसो. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी पी.जी. कॉलेज, फतेहपुर, उ.प्र.

जब भारत विभाजन हुआ था तब शायद ही किसी को यह लगा हो कि पाकिस्तान भी कभी दो टुकड़ों में बट जायेगा। क्योंकि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान में 80 % से अधिक मुसलमान थे। केवल 24 साल के बाद यानी 1971 का सच सबके सामने था। बांग्लादेश के निर्माण के साथ जिन्ना की “टू नेशन थ्योरी” असफल हो गयी। पाकिस्तान के निर्माण के समय से ही वहाँ उर्दू और बांग्ला भाषा के बीच संघर्ष चल रहा था। विलियम वान शिंडल ने इस सम्बन्ध में अपनी पुस्तक, “ए हिस्ट्री आफ बांग्लादेश” में लिखा है “पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच शुरूआती विवाद इसी वजह से हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान में न के बराबर बांग्ला भाषा को जानते थे। इन लोगों का मानना था कि बांग्ला पर हिन्दुओं का असर था। शायद यही वजह थी कि फरवरी 1948 में जब पाकिस्तानी असेम्बली में एक बंगाली सदस्य ने यह प्रस्ताव पेश किया कि उर्दू के साथ-साथ बांग्ला भाषा का इस्तेमाल हो। इस पर तत्कालीन पीएम0 लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान उप-महाद्वीप के करोड़ों मुसलमानों की मांग पर बना है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है, इसलिए यह अहम है कि पाकिस्तान की एक कॉमन भाषा हो जो केवल उर्दू हो सकती है।”¹ मार्च 1948 में पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ढाका दौरा पर गए थे वहाँ पर उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि “मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा केवल उर्दू होगी यदि आपको कोई गुमराह करता है तो वह पाकिस्तान का दुश्मन है। जहाँ तक राजकीय भाषा का सवाल है, वो केवल उर्दू है।” इससे पूर्वी पाकिस्तान में एक ऐतिहासिक भाषा आन्दोलन का जन्म हुआ। तनाव का एक कारण बंगाली महिलाओं का परम्परागत परिधान साड़ी था जिसे पश्चिमी पाकिस्तानी राजनेता और अधिकारी हिन्दुओं का परिधान मानते थे और घृणा की दृष्टि से देखते थे। ऐसा ही वर्णन दैनिक जागरण में किया गया है, “सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा एक दूसरे से अलग थे। दोनों जगह के समुदाय

अलग-अलग संस्कृति जी रहे थे। पूर्वी हिस्सा काफी हद तक समावेशी था तो पश्चिमी हिस्से को अमूमन संकीर्ण बना दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी प्रभावी थे और ये पूर्वी हिस्से के मुसलमानों को दोयम दर्जे का मानते थे क्योंकि पंजाबी मुसलमानों के अनुसार बंगाली मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू थे। इतना ही नहीं मछली और कपास के उत्पादन के कारण पूर्वी पाकिस्तान की आय अधिक थी, लेकिन खर्च पश्चिमी हिस्से में हो रहा था, इसका असर दोनों इलाकों के विकास पर पड़ा।”² पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए शेख मुजीब-उर-रहमान ने अपना छः सुत्रीय कार्यक्रम पेश किया। ये सूत्र निम्न थे –

2. छः सुत्रीय कार्यक्रम

1. एक महा संघ की स्थापना की जाये जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग-अलग प्रांत होने चाहिए।

2. संघीय सरकार के पास केवल विदेश और रक्षा सम्बन्धी शक्तियाँ हो और शेष सभी शक्तियाँ प्रांतों के पास होनी चाहिये।

3. दोनों प्रांतों की अलग-अलग मुद्रा होनी चाहिये जो स्वतंत्र रूप से विनिमेय होनी चाहियें। अलग दोनों प्रांतों की एक ही मुद्रा हो तो पूर्वी पाकिस्तान से पूंजी के पलायन को रोकने के लिए संवैधानिक प्रावधान हो।

4. केन्द्रीय सरकार के पास कर लगाने और राजस्व एकत्रित करने का अधिकार नहीं होना चाहिये, ये प्रांतों के पास होना चाहिये।

5. विदेशी मुद्रा अर्जन और विदेशी व्यापार का अधिकार प्रांतों के पास होना चाहिये।

6. पूर्वी पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए अपना अर्द्ध सैनिक/सुरक्षा बल होना चाहिये।

पाकिस्तानी सरकार ने इस प्रस्ताव को अलगाववादी कहकर खारिज कर दिया। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लिए यह स्वायत्तता का चार्टर और बांग्लादेश की मुक्ति आन्दोलन का आधार बना।

3. बांग्लादेश मुक्ति आन्दोलन

1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीब-उर-रहमान को यहाँ की कुल 169 सीटों में से 167 सीटों विजय प्राप्त हुई। सम्पूर्ण पाकिस्तान के स्तर पर शेख मुजीब-उर-रहमान को (313 सीटों में से 167 सीटें) स्पष्ट बहुमत मिला। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टों की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बहुमत से दूर रहे गयी। जुल्फिकार अली भुट्टों ने अन्य पार्टियों के नेताओं से मिलकर चुनाव परिणामों को मानने से मना कर दिया। जिसके कारण नेशनल असेम्बली की बैठक नहीं हो सकी। पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शसक याह्या, जुल्फिकार अली भुट्टों और अन्य नेता यह नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई नेता सम्पूर्ण पाकिस्तान पर शसन करें। इन षड्यंत्रों के कारण लोकतांत्रिक रूप से चुनी गयी अवामी लीग पार्टी को सत्ता का हस्तान्तरण नहीं हो सका। जिसके कारण शेख मुजीब-उर- रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान में एक असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। इससे ही एक मुक्ति वाहिनी (गोरिल्ला युद्ध संगठन) का जन्म हुआ। स्वतंत्र बांग्लादेश इस आन्दोलन की एक ही मांग थी। इस आन्दोलन का दमन करने के लिए दिनांक 25 मार्च 1971 को रात्रि में आपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया गया। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीब-उर-रहमान को गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व दूरदर्शन प्रसारण के माध्यम से बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी थी। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के द्वारा जनता के साथ घोर अन्याय अत्याचार और हिंसा की जा रही थी। इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट में बताया गया कि “जिस समय भारत बांग्लादेश मुक्ति आन्दोलन में कूदा उस

समय तक पाकिस्तानी फौज ने 25 लाख बांग्ला भाषी मुसलमानों एवं हिन्दुओं का नरसंहार कर चुकी थी, लाखों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो चुका था। पाकिस्तानी फौज बांग्ला भाषी मुसलमानों की नस्ल बदलने के लिए रेप कैम्प चला रही थी। इन कैम्पों में जन्में हजारों बच्चों के पुनर्वास के लिए बाद में बांग्लादेश की सरकार ने दत्तक ग्रहण कार्यक्रम चलाना पड़ा।”³ पाकिस्तानी सेना ने आपरेशन सर्च लाइट के दौरान हजारों बांग्ला भाषी मुसलमानों, हिन्दुओं और अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचने के लिए पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 1 करोड़ लोग शरणार्थी के रूप में भारत आ गया। भारत सरकार ने इन्हें मानवीय आधार पर इन्हें शरण दी और इस आन्दोलन को नैतिक समर्थन दिया। लेकिन इसके कारण भारत पर आर्थिक और सामाजिक बोझ पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पश्चिमी देशों एवं अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मुलाकात कर पश्चिमी पाकिस्तान पर दबाव डालकर पूर्वी पाकिस्तान की जनता को दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की अपील की। लेकिन पश्चिमी देशों और अमेरिका से कोई सहयोग नहीं मिला बल्कि पाकिस्तान को अमेरिका और चीन का कूटनीतिक सहयोग मिल रहा था। ऐसी परिस्थितियों में भारत और सोवियत संघ के बीच संधि का प्रेरणा बिन्दु अप्रत्यक्ष रूप से चीन बना। सन् 1969 में सोवियत संघ का चीन के साथ उसुरा नदी की सीमा को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया था। सोवियत संघ ने भारत सरकार के सामने संधि का प्रस्ताव रखा था। संधि का अधिकांश मसौदा 1969 तक तैयार हो चुका था। पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध मार्च 1971 में हुआ था। अमरीकी

विदेशमंत्री हेनरी किंसिंजर ने अपनी पुस्तक व्हाइट हाउस इयर्स 1979 में भारत के राजदूत लक्ष्मीकांत झा से कहा, “अगर भारत पाकिस्तान युद्ध में चीन हस्तक्षेप करता है तो अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा।”⁴ इससे भारत सरकार सावधान हो गयी इन्दिरा गांधी ने अपने अधिकारियों को सोवियत संघ के साथ सन्धि करने के लिए विचार करने के लिए कहा। हेनरी किंसिंजर की गुप्त बीजिंग यात्रा के ठीक एक महीने बाद 09 अगस्त 1971 को नई दिल्ली में श्रीमती इन्दिरा गांधी की उपस्थिति में भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और सोवियत संघ के विदेश मंत्री अंद्रेई ग्रोमिको ने भारत सोवियत शान्ति मैत्री और सहयोग संघ पर हस्ताक्षर किये। इस सम्बन्ध में वी0एन0 खन्ना एण्ड लिपक्षी अरोड़ा ने अपनी पुस्तक भारत की विदेश नीति में लिखा है, “सोवियत संघ ने भारत के पूर्व राजदूत डी.पी. धर अगस्त 1971 में वार्ता के लिए मास्को गये उसके बाद एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल नई दिल्ली आया। दोनों में वार्ता के बाद 09 अगस्त 1971 को 20 वर्ष के लिए एक शान्ति एवं मैत्री सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि पर भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और सोवियत संघ के विदेश मंत्री आन्द्रेई ग्रोमिको ने हस्ताक्षर किये।”⁵ इस संधि के माध्यम से भारत ने भविष्य में अमेरिका और चीन के हस्तक्षेप के स्थिति में सोवियत संघ से सैन्य सहयोग सुनिश्चित कर दिया।

पाकिस्तान अपनी आन्तरिक समस्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार मानता था और इसी सोच के तहत उसने 03 दिसम्बर 1971 को सायं 5:30 बजे आपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवन्तीपुर, जोधपुर, अम्बाला और आगरा आदि सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। ऐसी स्थिति में

भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय नौ सेना ने भीषण पलटवार करते हुए कराँची, चटगाव और ढाका के बन्दरगाहों में अनेक युद्धपोत, विध्वंसक और माइन स्वीपर को नष्ट कर दिया। कराची के विशाल तेल भण्डार को नष्ट कर दिया जिसके कारण कराची में कई दिनों तक आग लगी रही और धूँआ उठता रहा। पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी पी.एन.एस. गाजी को भारत के विमान वाहक पोत आई.एन.एस. विक्रान्त (जो बंगाल की खाड़ी में नाकाबंदी किये था) को नष्ट करने के लिए भेजा था। लेकिन भारतीय नौ सेना ने उसे अपने जाल में फसाकर आई.एन.एस. राजपूत ने विशखापटनम् के पास पाकिस्तानी पनडुब्बी को नष्ट कर दिया। भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के सरगोधा, मियाँवाली, चकलाला, मसरूर, मुरीदके, रफीकी और शंकरगढ़ आदि वायु ठिकानों को नष्ट कर दिया। भारतीय थल सेना ने कार्यवाही करते हुए पाकिस्तान के शंकरगढ़ सेक्टर और पाक अधिकृत कश्मीर में बहुत नुकसान पहुँचाया और काफी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।

06 दिसम्बर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को एक सम्प्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। इन युद्ध की परिस्थितियों में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए 10 दिसम्बर 1971 को श्रीमती इन्दिरा गांधी और बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति नजरूल इस्लाम द्वारा हस्ताक्षरित सन्धि में यह व्यवस्था की गयी कि बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय सेना के अधीन एक कमान स्थापित की जायेगी। भारत ने यह भी वचन दिया कि जैसे ही बांग्लादेश में सामान्य स्थिति बहाल हो जायेगी वैसे ही भारतीय सैनिक स्वदेश लौट आयेंगे। भारत ने बांग्लादेश की प्रादेशिक अखण्डता का वचन दिया और यह भी

आश्वासन दिया कि नये बांग्लादेश के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हार से बचाने के लिए 04 दिसम्बर-12 दिसम्बर 1971 के मध्य केवल 9 दिन के अन्दर संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका द्वारा तीन बार युद्ध विराम प्रस्ताव लाया गया जिसे सोवियत संघ ने तीनों बार वीटो कर दिया, जिससे प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इस दौरान अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन तटस्थ रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दूसरी बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व जुल्फिकार अली भुट्टों और अमेरिका का प्रतिनिधित्व जार्ज बुश सीनियर कर रहे थे। बैठक में तीखी बहस हो रही थी। इस सम्बन्ध में प्रोफेसर गैरी जे0 वैस ने अपनी पुस्तक में लिखा है, “जब बुश ने निक्सन और हेनरी किसिंजर के निर्देश पर लड़ाई में भारत की मंशा के बारे में सवाल किया तो स्वर्ण सिंह ने उन्हीं से सवाल पूछ डाला की वियतनाम युद्ध में अमेरिका की क्या मंशा है।”⁶ जब सोवियत संघ ने युद्ध विराम प्रस्ताव पर दूसरी बार वीटो किया तो अमेरिकी विदेशमंत्री बहुत नाराज हो गये। इस सम्बन्ध में स्वयं हेनरी किसिंजर ने अपनी पुस्तक व्हाइट हाउस डायरी-1979 में लिखा है, “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब सोवियत संघ ने दूसरी बार युद्ध विराम प्रस्ताव पर वीटो कर भारत को बचाया, इससे हेनरी किसिंजर इतना नाराज हो गए कि उन्होंने निक्सन से पूछे बिना ही अगले कुछ दिनों में सोवियत संघ के साथ होने वाली शिखर वार्ता को ही रद्द करने की धमकी दे डाली।”⁷

संयुक्त राष्ट्र संघ की उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में तीव्रता और आक्रमकता के साथ कार्यवाही करते हुए भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान की वायु सेना को पंगु बना दिया। 07 दिसम्बर 1971 को भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के जेसौर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया पाकिस्तानी सेना ने ढाका की ओर जाने वाले सभी रास्तों के पुलों को नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने मेघना एवं अन्य नदियों के पार भारतीय सैनिकों और भारतीय हथियारों को पहुंचाने के लिए हेलीकोप्टरों का प्रयोग किया। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना पर गोरिल्ला हमला कर उनकी रसद आपूर्ति लाइन को काट दिया। लेफ्टिनेन्ट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पूरब, उत्तर और पश्चिम तीनों तरफ से तेजी से ढाका की तरफ कूँच कर दिया। भारतीय सेना ने 4-5 दिसम्बर 1971 की रात को सिलहट के पास स्थित गाजीपुर टी स्टेट को अपने कब्जे में ले लिया। 09 दिसम्बर को भारतीय सेना ने अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया, इस दौरान रावलपिंडी और ढाका के बीच संचार सम्पर्क टूट गया। पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर मलिक ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायक सचिव पॉल मार्क हेनरी के माध्यम से युद्ध विराम का प्रस्ताव भारत भिजवाया।

अमेरिका ने 10 दिसम्बर 1971 को भारत को युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने के लिए अपना 7वां बेड़ा को बंगाल की खाड़ी में भेजने की घोषणा कर दी। ऐसी स्थिति में भारत ने सोवियत संघ से मदद मांगी। सोवियत संघ ने अमेरिका के 7वें बेड़े का मुकाबला करने के लिए अपना पैसिफिक फ्लीट के परमाणु सक्षम जहाजों और पनडुब्बियों को

ब्लादिवोस्तोक से भेज दिया। सोवियत संघ के युद्ध पोत और पनडुब्बियों ने अमेरिका का 7वें बेड़े को आगे नहीं बढ़ने दिया और तब तक इसका पीछा किया जब तक 7वां बेड़ा हिन्द महासागर से बाहर नहीं चला गया। सोवियत संघ ने भारत को परमाणु सैन्य सामग्री को अपने कजाकिस्तान के सैन्य अड्डा से कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर भेजने का प्रस्ताव भी दिया।

7वें बेड़े की खबर सुनकर जनरल नियाजी के तेवर बदल गये, जो कल तक युद्ध विराम की अपील कर रहा था वही नियाजी खान 12 दिसम्बर 1971 को पत्रकारों के सवालियों का जवाब देते हुए कहा कि “आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ना है..... ढाका मेरी लाश पर गिरेगा। फिर अपने सीने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें इस पर टैंक चलाना होगा।”

4. बांग्लादेश: एक सम्प्रभु राष्ट्र का उदय

14 दिसम्बर 1971 को भारतीय वायु सेना की पूर्वी कमान के रेडियो एवं वायरलेस यूनिट में पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के बीच टेलीफोन पर बातचीत को पकड़ लिया। पूर्वी कमान के सिग्नल इंटेलिजेन्स के प्रमुख लेफ्टिनेन्ट कर्नल पी0सी0 भल्ला ने इस बातचीत को पूर्वी कमान के चीफ आफ स्टाफ मेजर जनरल जैकब को बताया मेजर जनरल ने तुरंत पूर्वी वायु सेना कमान शिलांग के प्रमुख एयरवाइस मार्शल श्री देवेशर से बात कर ढाका में गवर्नर हाउस में मीटिंग के दौरान ही हमला करने की रणनीति बनाई। इसके अनुसार गुवाहटी से विंग कमाण्डर बिश्रोई और हासिमारा हवाई अड्डे से विंग कमाण्डर एस0के0 कौल ने गवर्नर हाउस पर हमला कर दिया। इस हमले में गवर्नर हाउस की मुख्य इमारत कि छत नष्ट हो गयी, लोग सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगे। इस सम्बन्ध में

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के प्रतिनिधि जान कैली ने अपनी पुस्तक श्री डेज इन ढाका में लिखा है “हमले के दौरान मेरा पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य सचिव मुजफ्फर हुसैन से सामना हुआ उनका रंग पीला पड़ा हुआ था। मैं बीस गज दूर बंकर की तरफ भागा मेरे सामने से मेजर जनरल राव फरमान अली दौड़ते हुए निकले वो भी बचने के लिए आड ढूँढ रहे थे। दौड़ते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं।”⁸ भारतीय हमला के प्रभाव के बारे में लंदन आब्जर्वर के संवाददाता गविन यंग ने अपनी पुस्तक गविन यंग वल्डस अपार्ट ट्रेवल्स इन वार एण्ड पीस में लिखा है। “भारतीय जेटों ने गुजरते हुए हमला किया, धरती फटी और हिली भी। मलिक के मुँह से निकला अब हम भी शरणार्थी है..... मलिक ने पेन निकाला और कापते हुए हाथों से एक कागज पर कुछ लिखा। कैली और मैंने देखा कि यह मलिक का इस्तीफा था, अभी हमला जारी था। मलिक ने अपने जूते उतारे और बगल के गुसलखाने में अपने हाथ पैर धोये और रुमाल से सिर ढका और बंकर के एक कोने में नमाज पढ़ने लगे। यह गवर्मेन्ट हाउस का अन्त था, यह पूर्वी पाकिस्तान सरकार का भी अन्त था।”⁹ इस युद्ध में भारत के लगभग 3630 सैनिक शहीद हुए और 9856 सैनिक घायल हुए। भारत ने इस युद्ध में सात हजार करोड़ रुपये खर्च किये।

16 दिसम्बर 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान पाकिस्तानी सेना के 93000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी जनरल अमीर खान नियाजी ने भारतीय सेना के चीफ आफ स्टाफ जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार दक्षिण एशिया में बांग्लादेश नाम का एक सम्प्रभु राष्ट्र का जन्म हुआ।

5. निष्कर्ष

भारत ने मानवीय आधार पर इस युद्ध में भाग लिया था। ऐसा ही डोम मारेन्स ने अपनी पुस्तक मिसेज गांधी-1980 में लिखा है, “भारत ने युद्ध में पूरी तरह मानवीय कारणों से भाग लिया और भारत पूरी आबादी को नष्ट होते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था।”¹⁰ अधिकांश पश्चिमी और चीन की मीडिया ने 1971 के युद्ध में भारत को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया। अमेरिका की खुफिया विभाग की रिपोर्ट ऐसा ही लिखा है, “मिसेज गांधी को जीत का पूरा भरोसा था जो भारत को दक्षिण एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। उनका यह भी मानना था कि युद्ध से पाकिस्तान सैन्य शसन का अन्त होगा और लोकतांत्रिक शासन स्थापित होगा।”¹¹ इसी प्रकार का वर्णन प्रो0 गैरी जे0 बैस ने अपनी पुस्तक द ब्लड टेलिग्राम: इण्डियाज सीक्रेट वार इन ईस्ट पाकिस्तान में लिखा है, “भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर बंगाली विद्रोह को गुप्त रूप से प्रायोजित करने के लिए भारी संसाधनों को समर्पित किया, गोरिल्लाओं को हथियार प्रशिक्षण शिविर और खुली सीमाओं के पार आवागमन प्रदान किया।”¹²

“भारत ने पश्चिमी देशों से आग्रह किया कि पाकिस्तान पर दबाव डालकर शेख मुजीब-उर-रहमान को पाकिस्तानी जेल से आजाद कराये अंततः 08 जनवरी 1972 को शेख मुजीब-उर-रहमान को मुक्ति कर दिया गया। 10 जनवरी 1972 को बांग्लादेश जाते समय

दिल्ली पहुँचे यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने भारत को हार्दिक धन्यवाद दिया, विशेषकर उन बलिदानों के लिए जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय वीरों ने दिए थे। ढाका जाकर उन्होंने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का पद-भार ग्रहण कर लिया।”

सन्दर्भ सूची -

1. Van Schendel, W. (2009). A history of Bangladesh. Cambridge University Press.
2. दैनिक जागरण. (2026, 9 जनवरी).
3. दैनिक जागरण. (2026, 10 जनवरी).
4. Kissinger, H. A. (1982). White House Years. Little, Brown and Company.
5. Khanna, V. N., & Arora, L. (n.d.). भारत की विदेश नीति.
6. Bass, G. J. (2013). The Blood Telegram: Nixon
7. Kissinger, H. A. (1982). White House Years. Little, Brown and Company.
8. Kelly, J. (n.d.). Three Days in Dhaka.
9. Young, G. (1993). Worlds Apart: Travels, War and Peace
10. Jolly, D. M. (n.d.). Mrs. Gandhi
11. Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency.
12. Bass, G. J. (2013). The Blood Telegram: Nixon, Kissinger, and a forgotten genocide. Alfred A. Knopf.